भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2419

जिसका उत्तर 18 दिसम्बर, 2023/27 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया

देश भर में यूपीआई लेन-देन

2419. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में यूपीआई लेन-देन धीरे-धीरे बहुत बढ़ रहा है और नकदी के परिचालन में अंततः गिरावट आ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में लोगों से केवल डिजिटल माध्यम से भुगतान करने का आग्रह किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;

(ग) लोगों को नकद भुगतान करने से रोकने और इसके स्थान पर डिजिटल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने रूपये क्रेडिट कार्ड को यूपीआई खातों से जोड़ने की अनुमति दे दी है ताकि छोटे लेन-देन के लिए प्लास्टिक कार्डों का उपयोग किया जा सके;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह उपभोक्ताओं के लिए किस प्रकार लाभकारी होगा; और

(च) डिजिटल भुगतान पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए/किए जा रहे अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क): यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेन-देन की संख्या, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 में 92 करोड़ थी वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर 8,375 करोड़ हो गई है, इस प्रकार इसमें 147% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर (सीएजीआर) से वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, यूपीआई लेन-देन का मूल्य, जो 168% सीएजीआर पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में 1 लाख रुपये करोड़ था, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर 139 लाख करोड़ रुपये हो गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 11 दिसंबर, 2023 तक यूपीआई के माध्यम से 8,572 करोड़ लेन-देन हुए हैं। देश में डिजिटल भुगतान लेन-देन की समग्र वृद्धि में यूपीआई, एक प्रमुख प्रेरक बल रही है, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में 62% डिजिटल भुगतान लेन-देन हुए हैं। प्रचलन में रहे बैंक नोटों के मूल्य में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि में कमी आई है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रचलन में रहे नोटो का मूल्य 9.9% था, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में घटकर 7.8% हो गया है।

(ख) और (ग) और (च): डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों में *अन्य बातों के साथ-साथ* (i) रूपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (पी2एम) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना (ii) भुगतान स्वीकार करने सम्बंधी अवसंरचना ढांचे में सुधार के लिए विभिन्न हितधारकों को

भारत सरकार द्वारा परामर्श जारी करना (iii) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए डिजिटल भुगतान लेन-देन और कारोबारियों को शामिल करने सम्बंधी वार्षिक लक्ष्य का आवंटन और निगरानी (iv) प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए अभियान (पीएमजीदिशा) और (v) डिजिटल भुगतान हितधारकों और विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के साथ आयोजित अन्य प्रचार-प्रसार सम्बंधी गतिविधियां शामिल हैं।

ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, आरबीआई डिजिटल भुगतान उत्पादों, धोखाधड़ी और जोखिम को कम करने और शिकायत निवारण के बारे में जागरूकता पर जोर देने के साथ-साथ देश भर में (i) इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण (ई-बात) कार्यक्रम (ii) डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह (iii) मिशन 'हर पेमेंट डिजिटल' कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है जिसका उद्देश्य भारत के प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल भुगतान की जानकारी देना है। आरबीआई ने आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में '75 डिजिटल गांव' कार्यक्रम भी शुरू किया है और विभिन्न डिजिटल भुगतान पहल जिनमें ग्राहकों की संरक्षा, सुरक्षा और सुविधा को कवर किया गया है के बारे में जनता के बीच जागरूकता लाने के लिए 'आरबीआई कहता है' के टैग के तहत मल्टीमीडिया चैनल/प्लेटफॉर्म आधारित जन जागरूकता अभियान भी चलाया गया है।

(घ) और (ङ): भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने की अनुमति दे दी है। उपभोक्ताओं को होने वाले लाभों में (i) एक बार रुपे क्रेडिट कार्ड यूपीआई से लिंक हो जाने पर, यूपीआई क्यूआर के माध्यम से इसका उपयोग करने के लिए प्लास्टिक कार्ड ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी (ii) ग्राहकों को क्यूआर कोड वाले लघु व्यापरिक आउटलेट्स पर भी क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके व्यय करने में सक्षम बनाना शामिल है।

******